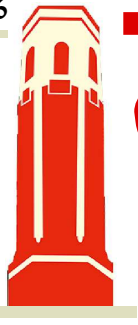


- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 263
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00



दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

भाजपा में दलबदलुओं पर तंज से सियासी भूचाल

♦ उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ने वाली है टिकट की जंग

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट की जंग तेज होने के संकेत मिलने लगे हैं। सत्ता और संगठन में अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे नेताओं के बीच अब दलबदल का मुद्दा भी नए सिरे से गरमाने लगा है। कांग्रेस और दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं की राजनीतिक हैसियत को लेकर प्रदेश में चल रही चर्चाओं के बीच पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान की टिप्पणी ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। पशु मेले में लूले-लंगड़े गधे-घोड़े खरीदे जाने जैसे तंज ने उन नेताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो दूसरे दलों से भाजपा में आए और अब आगामी चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं।

2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य दलों के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कई नेता बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से अनेक नेता अब अपनी-अपनी विधानसभा सीटों पर सक्रिय हैं और अगले चुनाव में भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

लेकिन भाजपा के भीतर टिकट के दावेदारों की लंबी कतार और पुराने कार्यकर्ताओं की अपनी दावेदारी के बीच इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य आसान नजर नहीं आ रहा है। दलबदल कर भाजपा में आए नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में अपनी स्वीकार्यता साबित करने की है। एक तरफ उन्हें अपने पुराने राजनीतिक जनाधार और समर्थकों को साथ बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के बीच जगह बनानी है, जो वर्षों से संगठन के लिए काम कर रहे हैं और टिकट पर अपना स्वाभाविक दावा मानते हैं।

ऐसे में मनवीर सिंह चौहान की टिप्पणी को केवल एक राजनीतिक तंज मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। चुनाव से पहले टिकट की दावेदारी के बीच इस तरह की टिप्पणी दलबदलुओं की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। हालांकि, इस बयान से सभी दलबदलुओं के टिकट कटने या पार्टी में उनकी भूमिका खत्म होने का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना साफ है कि टिकट की लड़ाई में पुराने और नए नेताओं के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है। भाजपा में टिकट



♦ दिल्ली से दून तक संगठन में पुराने बनाम नए भाजपाइयों की लड़ाई के आसार
♦ भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के बयान ने उत्तराखंड में गरमाई सियासत
♦ दलबदलुओं के टिकट पर सवाल, सरकार से संगठन तक दायित्वधारियों की लंबी फौज

वितरण का फैसला केवल किसी नेता की व्यक्तिगत दावेदारी से तय नहीं होता। संगठन की रणनीति, चुनावी जीत की संभावना, स्थानीय समीकरण और केंद्रीय नेतृत्व का आकलन इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नेताओं की

सक्रियता बढ़ने के साथ दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज होने लगी है।

दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी में उनकी राजनीतिक उपयोगिता और स्थानीय प्रभाव के आधार पर उन्हें अवसर मिलेगा। वहीं, पुराने कार्यकर्ता यह सवाल उठा सकते हैं कि लंबे समय से संगठन के लिए काम करने के बावजूद टिकट के समय बाहरी नेताओं को प्राथमिकता क्यों दी जाए। यही विरोधाभास आगामी चुनाव में भाजपा के लिए आंतरिक चुनौती बन सकता है।

भाजपा की सियासत में केवल विधानसभा टिकट ही दावेदारी का केंद्र नहीं है। सरकार में दायित्व, संगठन में पद और विभिन्न संस्थाओं में नियुक्तियों की उम्मीद लगाए नेताओं की भी लंबी कतार है। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी के सामने सभी महत्वाकांक्षाओं को साधने की चुनौती होगी। जिन नेताओं को टिकट की उम्मीद है, वे अपनी विधानसभा में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। जिन्हें संगठन या सरकार में जिम्मेदारी मिलने की आशा है, वह भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। दलबदलुओं को लेकर सामने आया

तंज इस व्यापक प्रतिस्पर्धा के बीच और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

उत्तराखंड में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चुनावी तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी के लिए केवल विपक्ष को चुनौती देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अपने भीतर टिकट के दावेदारों और अलग-अलग गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। दलबदलुओं को लेकर उठी बहस आने वाले दिनों में कितना राजनीतिक रूप लेती है, यह पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया और टिकट वितरण की रणनीति से स्पष्ट होगा। फिलहाल सवाल यही है कि दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर पार्टी कितना जोखिम लेगी और कितने पुराने कार्यकर्ताओं की दावेदारी को प्राथमिकता देगी। 2027 के चुनाव में भाजपा की असली परीक्षा केवल सीटें जीतने की नहीं, बल्कि टिकट की दौड़ में अपने ही नेताओं के बीच पैदा होने वाले असंतोष को संभालने की भी होगी। मनवीर चौहान की टिप्पणी ने इस चुनौती को चुनावी तैयारियों के बीच चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

सीजेपी के सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को 5 दिन की जेल

संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली में जंतर-मंतर मामले में सीजेपी के सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को 5 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। तीनों को एक दिन पहले जंतर-मंतर में घुसने के मामले में कस्टडी में लिया गया था। रात करीब 3 बजे उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई और आज सुबह पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने इससे पहले सोशल मीडिया पर तीनों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। उनके मुताबिक सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया। तीनों पर बिना इजाजत जंतर-मंतर में घुसने, बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं।

रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि तीनों को देर रात तक अपने वकीलों से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने



यह भी कहा कि रात करीब 3 बजे उन्हें एक प्राइवेट वैन से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया गया था। इसके बाद सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, जहां से तीनों को 5 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज

दिया गया।

सौरव दास और आशुतोष रांका को इससे पहले 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। उनके साथ सीजेपी के अभिजीत दीपके

भी पकड़े गए थे। 11 अक्टूबर को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीनों को एक साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखने की शर्त पर रिहा किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसके लिए 250 हजार का बॉन्ड भरवाया गया था। लेकिन 13 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका फिर जंतर-मंतर पहुंचे। पुलिस ने बिना अनुमति प्रवेश करने और सरकारी काम में बाधा डालने के साथ बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। इस बार उनके साथ अजिंक्य शिंदे को भी हिरासत में लिया गया।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी। अभिजीत दीपके ने पोस्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि आशुतोष और सौरव का अपराध सिर्फ जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि असहमति की आवाज को दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।

दून वैली मेल

संपादकीय

बेमौसम बारिश, बेबस व्यवस्था

मौसम बदल रहा है, बारिश का मिजाज बदल रहा है, आपदाओं का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन हमारी व्यवस्था की कार्यशैली नहीं बदल रही। बेमौसम बारिश एक बार फिर प्रकृति की अनिश्चितता और सरकारी तैयारियों के दावों के बीच का अंतर उजागर कर रही है। खेतों में किसान की मेहनत पर पानी फिर रहा है, सड़कों पर आवाजाही संकट में पड़ रही है और आम आदमी की दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो रही है। इसके बावजूद सवाल वही पुराना है- क्या हमारी सरकारें हर संकट के बाद नुकसान गिनने और राहत के आश्वासन देने के लिए ही तैयार रहती हैं, या संकट आने से पहले उससे निपटने की भी कोई ठोस व्यवस्था है? उत्तराखंड में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है। पहाड़ की भौगोलिक संवेदनशीलता, कमजोर संपर्क मार्ग, सीमित कृषि भूमि और गांवों तक पहुंचने वाली बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियां किसी से छिपी नहीं हैं। यहां बारिश केवल छाता निकालने या कुछ घंटे घर में बैठने का मामला नहीं है। कई इलाकों में यह सड़क संपर्क टूटने, खेतों को नुकसान पहुंचने और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच बाधित होने का कारण बन सकती है। इसके बावजूद हर बार बारिश के बाद वही तस्वीर सामने आती है। उत्तराखंड के संदर्भ में समस्या केवल मौसम की नहीं, विकास की दिशा और नियोजन की भी है। पहाड़ों में निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, जल निकासी और ढलानों की स्थिरता जैसे विषयों पर पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई, तो बारिश का असर और गंभीर हो सकता है। मैदानों में नालों और प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों पर अतिक्रमण तथा अनियोजित निर्माण जलभराव की समस्या बढ़ा सकते हैं। यह मान लेना आसान है कि बारिश असामान्य थी, इसलिए नुकसान हुआ। लेकिन हर बार मौसम को दोष देकर व्यवस्था की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। जहां मानवीय लापरवाही नुकसान बढ़ाती है, वहां जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन की असली परीक्षा प्रेस विज्ञप्तियों, बैठकों और समीक्षा के दौरों में नहीं होती। उसकी परीक्षा तब होती है, जब किसी गांव का संपर्क टूटता है, किसी किसान की फसल बर्बाद होती है या किसी सड़क पर आवाजाही जोखिमपूर्ण हो जाती है। सवाल यह है कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कितनी प्रभावी है? नालों की सफाई समय पर हुई या नहीं? सड़कों और पुलों की सुरक्षा का नियमित निरीक्षण किया गया या नहीं? चेतावनी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने क्या कदम उठाए? इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए। जवाबदेही के बिना आपदा प्रबंधन भी एक सरकारी औपचारिकता बनकर रह जाता है। यह भी समझना होगा कि मौसम का पूर्वानुमान जारी कर देना ही जिम्मेदारी पूरी कर देना नहीं है। चेतावनी तभी उपयोगी है, जब वह समय पर किसान, ग्रामीण, यात्री और स्थानीय प्रशासन तक पहुंचे तथा उसके आधार पर कार्रवाई हो। मौसम विभाग की सूचना के बाद भी यदि जोखिम वाले क्षेत्रों में आवश्यक सावधानी नहीं बरती जाती, तो सूचना तंत्र और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच की खाई पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार को बताना चाहिए कि चेतावनियों को जमीन पर उतारने के लिए क्या व्यवस्था है और उसकी निगरानी कौन करता है। बदलते मौसम के दौर में सरकारों को अपनी प्राथमिकताएं भी बदलनी होंगी। विकास का अर्थ केवल नई सड़कों का निर्माण, बड़ी परियोजनाओं की घोषणा या निवेश के आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं है। विकास का असली अर्थ ऐसी सड़कें, ऐसी जल निकासी व्यवस्था, ऐसी कृषि नीति और ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है, जो संकट के समय लोगों का साथ दे सके। यदि हर बारिश के बाद सड़कें क्षतिग्रस्त हों, खेतों में नुकसान हो और लोगों को राहत के लिए भटकना पड़े, तो विकास के दावों की समीक्षा जरूरी हो जाती है। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं के जोखिम को भी अब गंभीरता से लेना होगा। हर असामान्य बारिश को बिना वैज्ञानिक प्रमाण जलवायु परिवर्तन का परिणाम बताना उचित नहीं, लेकिन बदलती मौसमी परिस्थितियों के बीच जोखिम कम करने की तैयारी टालना भी समझदारी नहीं है। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में स्थानीय मौसम के आंकड़ों, भौगोलिक परिस्थितियों और पुराने नुकसान के आधार पर दीर्घकालिक योजनाएं बननी चाहिए। खेती को मौसम के अनुकूल बनाने, जल निकासी सुधारने, ढलानों की सुरक्षा करने और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने में निवेश किया जाना चाहिए। सरकार को अब स्पष्ट समयसीमा के साथ कार्रवाई करनी होगी। प्रभावित फसलों का पारदर्शी सर्वेक्षण हो, पात्र किसानों को समय पर सहायता मिले, संवेदनशील सड़कों और पुलों का सुरक्षा परीक्षण हो तथा जल निकासी व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की जाए। जिन विभागों का काम केवल कागजों में पूरा होता है, उनके प्रदर्शन की समीक्षा भी होनी चाहिए। आपदा के बाद राहत देना आवश्यक है, लेकिन उससे कहीं अधिक जरूरी है कि पहले से किए जा सकने वाले उपायों में लापरवाही न हो। प्रकृति के सामने मनुष्य की सीमाएं हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही को प्रकृति की मजबूरी बताकर छिपाया नहीं जा सकता। बारिश कब और कितनी होगी, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन उससे निपटने की तैयारी, समय पर चेतावनी, सुरक्षित निर्माण, किसानों की सहायता और राहत व्यवस्था की गति हमारे नियंत्रण में हैं। बेमौसम बारिश ने मौसम का मिजाज दिखाया है, अब सरकार को अपनी कार्यशैली का हिसाब देना चाहिए। हर बार बारिश के बाद जागना, नुकसान गिनना और राहत का भरोसा देना पर्याप्त नहीं है। जनता को ऐसी व्यवस्था चाहिए, जो संकट के समय दिखाई दे, सिर्फ कागजों और घोषणाओं में नहीं, जमीन पर। क्योंकि सवाल बारिश का नहीं, उस व्यवस्था का है जो हर नई चुनौती के सामने पुरानी गलतियां दोहराती है।

चुनावी रण की तैयारी में जुटा भारत निर्वाचन आयोग

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 का रण सजने से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। प्रदेश में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने प्रशासनिक मशीनरी से लेकर सुरक्षा तंत्र तक की तैयारियों की समीक्षा की। देहरादून में आयोजित दो दिवसीय उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की तैयारियों का खाका प्रस्तुत किया, वहीं केंद्र और राज्य सरकार की 21 प्रवर्तन एजेंसियों ने भी चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। आयोग ने अब तक की तैयारियों पर संतोष जताते हुए सभी अधिकारियों को निर्धारित चुनावी योजना के अनुसार समयबद्ध ढंग से काम करने के निर्देश दिए।

बैठक में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल, महानिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी सीमा खन्ना और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चुनावी तैयारियों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया से जुड़े विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा चुनाव से पहले जरूरी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करना रहा। बैठक के पहले दिन जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन

अधिकारियों और जिला ईवीएम नोडल अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ईवीएम की जांच और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। दूसरे दिन सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में चल रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी आयोग के समक्ष रखी। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा बलों की तैनाती की

♦उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने परखी तैयारियां
♦ईवीएम से लेकर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा तक की विस्तृत समीक्षा की
♦सरकार की 21 प्रवर्तन एजेंसियों ने भी चुनावी तैयारियों की जानकारी दी

योजना, अपराध की स्थिति और कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया। चुनाव के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना आयोग की तैयारियों का अहम हिस्सा है।

चुनाव के दौरान धनबल और अन्य अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने में प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बैठक में अर्द्धसैनिक बलों, आबकारी, वस्तु एवं सेवा कर, परिवहन, वन विभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सीमा शुल्क विभाग सहित 21 एजेंसियों ने अपनी तैयारियों की जानकारी दी। इन एजेंसियों के बीच समन्वय का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि चुनाव के दौरान अवैध

नकदी, शराब और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल पर निगरानी रखने के साथ सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटना भी जरूरी होता है। आयोग की समीक्षा का मकसद चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है।

विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण और पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना भी अहम विषय है। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता चिह्नित हुए हैं, जिनका सत्यापन नहीं हो पाया। निर्वाचन विभाग ने ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने और पात्र लोगों को सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर देने के लिए अभियान शुरू किया है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलना है, जबकि संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2027 को निर्धारित है।

ऐसे में आयोग के सामने चुनौती केवल मतदान केंद्रों और सुरक्षा व्यवस्था को तैयार करने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि कोई पात्र मतदाता प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। मतदाता सूची की शुद्धता, ईवीएम की जांच, अधिकारियों का प्रशिक्षण और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय चुनाव की विश्वसनीयता के लिए निर्णायक होंगे। दो दिवसीय समीक्षा बैठक के समापन पर

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान के साथ मना 'भव्य रामलीला महोत्सव'



हमारे संवाददाता देहरादून। श्री रामकृष्ण लीला समिति द्वारा आयोजित 'भव्य रामलीला महोत्सव-2026' का तृतीय दिवस 'राज्य आंदोलनकारी सम्मान दिवस' के रूप में मनाया गया। श्री गुरु नानक मैदान, रसकोर्स में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों एवं राज्य आंदोलनकारी मंच को सम्मानित कर उनके योगदान को नमन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत जी उपस्थित रहे। तृतीय दिवस पर सीता स्वयंवर, धनुष खंडन तथा परशुरामखलक्ष्मण संवाद का भव्य मंचन किया गया। रामखसीता विवाह के प्रसंग

में पूरे पंडाल में हुई पुष्पवर्षा ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और लेजर एंड साउंड शो ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

महोत्सव के तृतीय दिवस की रामलीला में सीता स्वयंवर का मनोहारी मंचन किया गया, जिसमें विभिन्न राजाओं के हास्यपूर्ण अभिनय ने दर्शकों का मनोरंजन किया। भगवान श्रीराम द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के दृश्य ने दर्शकों में उत्साह भर दिया। इसके पश्चात परशुरामखलक्ष्मण संवाद का प्रभावशाली मंचन हुआ, जिसमें कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय, पारंपरिक संवादों और पौराणिक चौपाइयों से दर्शकों को भावविभोर कर दिया। रामखसीता विवाह के प्रसंग में मंच से लेकर पूरे पंडाल में हुई पुष्पवर्षा ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

वहीं आधुनिक लेजर एवं साउंड शो ने पारंपरिक रामलीला को आकर्षक और भव्य स्वरूप प्रदान किया।

श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952, देहरादून के अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण लंबे संघर्ष, जनआंदोलन, त्याग और बलिदान का परिणाम है। राज्य निर्माण के संघर्ष में पूरे प्रदेश के आंदोलनकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। इसी उद्देश्य से महोत्सव के तृतीय दिवस को राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके योगदान को स्मरण करने के लिए समर्पित किया गया है।

पुलिस ने चार लोगों को लौटाए खोए मोबाइल फोन व नकदी

संवाददाता
टिहरी। पुलिस ने चार लोगों को खोए मोबाइल व नकदी वापस कर उनके चेहरे पर मुस्कराहट लोटाई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में टिहरी गढ़वाल पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के साथ-साथ आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिसकर्मियों ने कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी का परिचय देते हुए अलग-अलग स्थानों पर खोए हुए मोबाइल फोन, पर्स एवं नकदी को बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सकुशल सुपुर्द किया। सीईआईआर पोर्टल की मदद से रेलवे नवयुगा कंपनी में कार्यरत धनंजय साहनी निवासी मुजफ्फरनगर का गुम हुआ रेडमी नोट 14 5जी मोबाइल बरामद कर उन्हें सुपुर्द किया गया। थाना हिंडोलाखाल: मां चंद्रबदनी मंदिर में दर्शन करने आई प्रीति पुंडीर का मोबाइल फोन, पर्स मय 8,000 कहीं गिर गए थे, उपरोक्त खोया हुआ मोबाइल फोन एवं 8,000 की नकदी वाला पर्स पुलिस टीम ने तलाश कर उन्हें वापस लौटाया। थाना हिंडोलाखाल: मां चंद्रबदनी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु अभय प्रताप का स्मार्ट मोबाइल फोन मंदिर परिसर के आसपास कहीं गिर गया था जिसे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता से तलाश कर सकुशल वापस किया। जल पुलिस मुनि की रेती: नाव घाट मुनि की रेती पर ड्यूटी के दौरान जल पुलिस को एक मोबाइल फोन लावारिस अवस्था में मिला, जिसे पूछताछ/सत्यापन के उपरांत मोबाइल स्वामी राजू भाई निवासी गुजरात को लौटाया गया। अपना खोया हुआ मोबाइल, नकदी व सामान वापस मिलने पर सभी स्वामियों के चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्होंने टिहरी पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता एवं सराहनीय कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया। टिहरी पुलिस का यह प्रयास आमजन के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता एवं मानवीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। टिहरी पुलिस आमजन की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी सहायता एवं सेवा के लिए सदैव तत्पर है।



हनुमान अंश ने रिलीज के 67वें दिन 1.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया

संवाददाता
नई दिल्ली। फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। रिलीज के कई दिनों बाद भी फिल्म की कमाई की रफ्तार बनी हुई है। महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। फिल्म ने रिलीज के 67वें दिन भी करोड़ों में कमाई की। 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार से हर किसी को हैरान कर दिया है। रिलीज के 67वें दिन इसने 1.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं, इसने रविवार को इसकी कमाई 2.80 करोड़ रुपये रही थी। यानी कि पिछले दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। रिलीज के पहले दिन महज 10 लाख रुपये कमाने वाली इस फिल्म को शुरुआत में फ्लॉप माना जा रहा था, लेकिन वक्त के साथ इसकी कमाई ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बड़े बजट की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो खबर लिखे जाने तक 'हनुमान अंश' का भारत में कुल नेट कलेक्शन 335.74 करोड़ रुपये का हो गया है। यानी कि फिल्म रिलीज के 67 दिनों बाद भी छाई हुई है और दर्शकों का ध्यान खींच रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म कितना और कलेक्शन कर पाती है। विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिनेता शोभिनाव सत्या महाराज जी के किरदार में नजर आए हैं।



वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

बूथ से समाज तक पकड़ मजबूत करेगी भाजपा

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने अपने संगठनात्मक मोर्चों को सक्रिय करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी अब सरकार के जनकल्याणकारी कामों को जनता तक पहुंचाने के साथ सामाजिक समरसता के संदेश को भी राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में जुटी है। इसी रणनीति के तहत भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन ने अनुसूचित मोर्चा और युवा मोर्चा को सरकार की योजनाओं तथा पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धताओं को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बूथ संरचना मजबूत करने और समाज निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया है।

भाजपा की इस पहल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी जानती है कि चुनावी मुकाबले में केवल सरकार की उपलब्धियों का दावा करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन उपलब्धियों को विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पहुंचाना और उनके बीच संगठन की स्वीकार्यता बनाए रखना भी जरूरी है। अनुसूचित मोर्चा और युवा मोर्चा की भूमिका इसी लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अनुसूचित मोर्चा के माध्यम से भाजपा अनुसूचित समाज के बीच सरकारी योजनाओं, सामाजिक न्याय और समरसता से जुड़े अपने संदेश को मजबूत करना चाहती है। वहीं युवा मोर्चा को युवाओं के बीच संगठन की सक्रियता बढ़ाने और सरकार के कामकाज को लेकर संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इन दोनों मोर्चों की सक्रियता पार्टी के

लिए सामाजिक आधार को व्यापक बनाने और स्थानीय स्तर पर संपर्क बढ़ाने का माध्यम बन सकती है।

राजनीतिक दृष्टि से यह कवायद इसलिए भी अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सामाजिक समीकरणों और युवा मतदाताओं की भूमिका निर्णायक हो सकती है। भाजपा के सामने चुनौती यह होगी कि योजनाओं के प्रचार के साथ इन वर्गों की वास्तविक समस्याओं और अपेक्षाओं को भी संगठन के एजेंडे में जगह दी जाए। प्रदेश महामंत्री

◆ अनुसूचित और युवा मोर्चा को संगठन की धार बढ़ाने का जिम्मा
◆ सरकार की योजनाओं के प्रचार पर रहेगा संगठन का फोकस
◆ सामाजिक समरसता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने पर जोर

संगठन ने बूथ संरचना को मजबूत करने पर जोर देकर स्पष्ट किया कि पार्टी की चुनावी रणनीति का आधार जमीनी संगठन ही रहेगा। भाजपा की चुनावी कार्यशैली में बूथ स्तर की सक्रियता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। पार्टी का प्रयास है कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम सक्रिय रहे, लोगों से निरंतर संपर्क बना रहे और सरकार की योजनाओं की जानकारी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे।

लेकिन बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती केवल बैठकों और कार्यक्रमों से तय नहीं होगी। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनता के साथ संवाद और स्थानीय समस्याओं के समाधान में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। यही वह स्तर है, जहां सरकार के दावों और जनता के अनुभवों के बीच की दूरी सामने आती है। भाजपा सरकार के जनकल्याणकारी कामों को जनता के बीच स्थापित करने की तैयारी कर रही है, लेकिन आगामी चुनाव में विपक्ष भी सरकार को बेरोजगारी, पलायन, भर्ती

प्रक्रियाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण सुविधाओं जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। ऐसे में भाजपा के मोर्चों के सामने केवल उपलब्धियों का प्रचार करने की नहीं, बल्कि जनता के सवालों का जवाब देने की चुनौती भी होगी।

युवा मोर्चा के लिए रोजगार और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े सवाल अहम रहेंगे, जबकि अनुसूचित मोर्चा के सामने सामाजिक सम्मान, समान अवसर और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचने जैसे विषयों पर संवाद स्थापित करने की जरूरत होगी। यदि संगठन इन सवालों को गंभीरता से उठाता है, तो उसकी सक्रियता चुनावी प्रचार से आगे बढ़कर जनसंपर्क का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

भाजपा की यह कवायद बताती है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न मोर्चों की भूमिका तय करने में जुटी है। सरकार की योजनाओं का प्रचार, सामाजिक समरसता का संदेश और बूथ संरचना को मजबूत करने का लक्ष्य एक ही राजनीतिक रणनीति के अलग-अलग हिस्से हैं। अब देखना होगा कि अनुसूचित और युवा मोर्चा इन निर्देशों को धरातल पर किस तरह लागू करते हैं। संगठन के सामने असली कसौटी यह होगी कि वह सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ जनता की अपेक्षाओं और शिकायतों को भी कितनी गंभीरता से सुनता है। भाजपा ने मोर्चों को सक्रिय कर चुनावी तैयारी का संकेत दे दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार की उपलब्धियों का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की यह मुहिम जनता का भरोसा बढ़ाने में कितनी सफल होती है। 2027 की सियासी लड़ाई में बूथ की मजबूती के साथ सामाजिक स्वीकार्यता भी भाजपा के लिए उतनी ही अहम रहने वाली है।

क्षेत्राधिकारी टिहरी ने किया कोतवाली का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण

संवाददाता
टिहरी। क्षेत्राधिकारी टिहरी द्वारा नई टिहरी कोतवाली का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण कर लंबित विवेचाओं के त्वरित निस्तारण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिये।

आज यहां जनपद टिहरी गढ़वाल में पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में पुलिस थानों की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा एवं निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी टिहरी चंद्रमोहन सिंह द्वारा थाना कोतवाली नई टिहरी का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की विभिन्न व्यवस्थाओं, अभिलेखों के रखरखाव, पुलिस कार्यप्रणाली तथा अपराध नियंत्रण से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, हवालात, सीसीटीएनएस कार्यालय एवं थाने में संधारित विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। संबंधित कर्मचारियों को अभिलेखों का व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करने तथा सभी आवश्यक प्रविष्टियों को समय से अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए।

क्षेत्राधिकारी टिहरी ने थाने में पंजीकृत अभियोगों, लंबित विवेचनाओं एवं अन्य प्रकरणों की समीक्षा करते हुए विवेचकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित की जाए। विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकरण को लंबित न रखा जाए। उन्होंने महिला संबंधी अपराधों, साइबर अपराधों, चोरी एवं अन्य आपराधिक घटनाओं से संबंधित शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने तथा पीड़ितों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने तथा आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी टिहरी चंद्रमोहन सिंह ने पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के

साथ करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने थाने में आने वाले फरियादियों एवं आमजन के साथ शालीन व्यवहार करने, उनकी शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनने तथा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्यप्रणाली में अनुशासन, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक पुलिसकर्मी का दायित्व है कि वह आमजन के बीच सुरक्षा की भावना को मजबूत करे और पुलिस के प्रति विश्वास बनाए रखे। अर्द्धवार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य थाना स्तर पर पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर करना, अभिलेखों एवं संसाधनों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना तथा पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है। टिहरी गढ़वाल पुलिस आमजन की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार, अनुशासन एवं जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।



लाल, हरी, पीली शिमला मिर्च: हर रोज खाने के लिए हेल्थ के हिसाब से कौन सा है बेहतर

लाल, हरी और पीली शिमला मिर्च पोषण से भरपूर होता है। इसे आप रोजाना खा सकते हैं या नहीं? लाल, हरी और पीली इन तीनों शिमला मिर्च में से पोषण तत्व से भरपूर कौन सा है? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे हर रोज खाने में तीनों में से कौन सी वाली शिमला मिर्च सबसे बेहतर है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस आर्टिकल के जरिए देंगे। यदि आप हाई विटामिन ए और सी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो लाल शिमला मिर्च आपकी पसंदीदा पसंद हो सकती है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन के होता है।

लाल शिमला मिर्च
लाल शिमला मिर्च, सबसे अधिक परिपक्व होने के कारण, सबसे मीठी होती है और इसमें कुछ पोषक तत्वों का स्तर उच्चतम होता है। लाल शिमला मिर्च में हरे और पीले रंग की तुलना में अधिक विटामिन ए होता है। स्वस्थ त्वचा, दृष्टि और इम्युनिटी को बनाए रखने के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। इसके अलावा लाल शिमला मिर्च में आमतौर पर हरी और पीली मिर्च की तुलना में विटामिन सी का लेवल अधिक होता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्युनिटी को मजबूत करता है और शरीर को आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है।

पीली शिमला मिर्च
हरी शिमला मिर्च की कटाई पूरी तरह पकने से पहले की जाती है, इसलिए लाल शिमला मिर्च की तुलना में उनका स्वाद थोड़ा अधिक कड़वा होता है। हालाँकि, वे विटामिन के का उत्कृष्ट स्रोत हैं, जो रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लोबल ने बताया कि हरी शिमला मिर्च भी अच्छी मात्रा में विटामिन सी प्रदान करती है।

लाल शिमला मिर्च
परिपक्वता और पोषण सामग्री के मामले में पीली शिमला मिर्च लाल और हरे रंग के बीच में आती है। उनका स्वाद लाल शिमला मिर्च की तुलना में हल्का होता है लेकिन फिर भी मीठा स्वाद देता है। लाल और हरी शिमला मिर्च की तरह, पीली शिमला मिर्च भी विटामिन ए और सी से भरपूर होती है।

लाल शिमला मिर्च
स्वाद के मामले में अगर तीनों शिमला मिर्च की तुलना करें लाल शिमला मिर्च
ये सबसे मीठी होती हैं और इनका स्वाद थोड़ा फल जैसा होता है। वे उन व्यंजनों में अच्छा काम करते हैं जहां मीठा या धुएँ के रंग का स्वाद वांछित होता है, जैसे भुनी हुई सब्जियाँ या भरावा मिर्च।

पीली शिमला मिर्च
लाल मिर्च की तुलना में हरी मिर्च का स्वाद अधिक तीव्र और थोड़ा कड़वा होता है। इन्हें अक्सर फ्रैजिलास, स्टर्-फ्राई जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों में या सलाद में कुरकुरे व्यंजन के रूप में उपयोग किया जाता है।

हरी शिमला मिर्च
लाल मिर्च की तुलना में पीली मिर्च हल्का और मीठा स्वाद प्रदान करती है, जो उन्हें विभिन्न व्यंजनों के लिए एक बहुमुखी विकल्प बनाती है। वे उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो अपने व्यंजनों में सूक्ष्म स्वाद पसंद करते हैं।

लाल शिमला मिर्च
खाना पकाने में किया गया इस्तेमाल
लाल शिमला मिर्च
पकने के कारण, लाल मिर्च नरम होती है और भूनने और ग्रिल करने में अच्छी होती है। मीठे और रसदार कंठ के लिए इन्हें सलाद में कच्चा भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

पीली शिमला मिर्च
हरी मिर्च की बनावट मजबूत होती है, जो उन्हें उच्च तापमान पर पकाने के लिए उपयुक्त बनाती है। वे स्टर्-फ्राई में अपना आकार अच्छी तरह से बनाए रखते हैं और अक्सर पके हुए व्यंजनों में उपयोग किए जाते हैं।

लाल शिमला मिर्च
लाल और हरे रंग के बीच की बनावट के साथ, पीली मिर्च बहुमुखी होती है। इन्हें सलाद में कच्चा खाया जा सकता है या विभिन्न व्यंजनों में पकाया जा सकता है, जो मिठास और कुरकुरापन का संतुलन प्रदान करते हैं।

अमरूद के सेवन से कई बीमारियों का रिस्क कम हो सकता है!

फल पोषक तत्वों का भंडार होते हैं। इन्हें खाने से सेहत दुरुस्त रहती है। रोजाना फलों के सेवन से कई तरह की परेशानियां शरीर से दूर रहती हैं। फलों में प्राकृतिक तौर पर कम कैलोरी पाई जाती है, जो वजन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सभी फलों में अमरूद बेहद फायदेमंद होता है। इसके सेवन से कई बीमारियों का रिस्क कम हो सकता है। रोजाना इनके सेवन से वजन भी तेजी से कम होता है। चूंक सड़ियों में ये फल मिलता है तो इस वक्त करीब 3०-4० रु. किलो के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है। आइए जानते हैं वजन कम करने में अमरूद क्यों इतना फायदेमंद है।

कम कैलोरी
वेट लॉस में अमरूद आपकी काफी मदद कर सकता है। इसे खाने से पेट देर तक भरा रहता है। इसमें काफी कम कैलोरी पाई जाती है। एक अमरूद में केवल 37-55 कैलोरी ही होती है। इनमें विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए वजन कम करने में ये फायदेमंद होता है।

प्रोटीन से भरपूर
अमरूद में भरपूर प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन और फाइबर दोनों ही पचने में लंबा वक्त लेते हैं। इससे पेट काफी देर तक भरा



रहता है। अमरूद में हाई फाइबर होता है, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 1०० ग्राम अमरूद में 5.4 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो वजन कम करने में कारगर होता है।

शुगर और कोलेस्ट्रॉल कम करे
अमरूद कम जीआई वाला फल है, जो वेट मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है। यह ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता और हार्मोन को भी बैलेंस रखता है। डायबिटीज के मरीजों और बढ़े वजन वाले लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी काफी कम पाया जाता है, जो वजन

कम करने का अच्छा विकल्प हो सकता है।

लंबे समय तक भरा रहता है पेट
अमरूद में मौजूद गुण पेट को देर तक भरा रखने में मदद करते हैं, जिससे शरीर का फैट कम हो सकता है। वजन कम करना चाहते हैं तो नियमित तौर पर अमरूद का सेवन करना चाहिए। शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में अमरूद काफी अच्छा विकल्प माना जाता है। हालांकि, किसी तरह की बीमारी में इसे सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

गर्भावस्था में मछली खाने से तेज होता है बच्चों का दिमाग

मछली खाने से दिमाग तेज होने की बातें पहले भी सामने आती रही हैं, जिसकी पुष्टि एक नए शोध से भी हुई है। इसमें कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान मछली खाना आने वाली संतान के लिए फायदेमंद हो सकता है। शोध के मुताबिक, गर्भावस्था के दौरान मछली खाने से होने वाले बच्चे का मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। यह अध्ययन जापान के तोहोको विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने किया है। इसमें खुलासा हुआ है कि मस्तिष्क के विकास के लिए ओमेगा-6 और ओमेगा-3 का संतुलन जरूरी होता

है। मछली में मौजूद पोषक तत्व मस्तिष्क को तेज करने का काम करते हैं। इसलिए गर्भावस्था के दौरान मछली खाना बच्चे के मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तोहोको विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नोरिको सुमि ने बताया, “गर्भवती महिलाओं के लिए लिपिड (वसा) की संतुलित मात्रा का सेवन भ्रूण के मस्तिष्क विकास के लिए जरूरी होता है।” उन्होंने बताया, “लिपिड में मौजूद फैटी एसिड जैसे ओमेगा-6 और ओमेगा-3 जानवरों और मनुष्यों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में से हैं।” इस शोध

के लिए मादा चूहों पर परीक्षण किया गया था। मादा चूहों को जब ओमेगा-6 युक्त और ओमेगा-3 रहित आहार खिलाया गया तो उनकी संतानों ने छोटे मस्तिष्क के साथ जन्म लिया था। इसके अतिरिक्त उन संतानों में वयस्क होने पर असामान्य व्यवहार पाया गया। सूमी के मुताबिक, “चूहों के मस्तिष्क में असमानता की वजह भ्रूण के मस्तिष्क की मूल कोशिकाओं का समय से पहले बढ़ा होना है। यह स्थिति ओमेगा-6 और ओमेगा-3 फैटी एसिड के असंतुलन से होती है।”

शब्द सामर्थ्य -055

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. भारत के वर्तमान वित्तमंत्री 6. हित, उपकार 7. असमान, पूर्वोत्तर का एक राज्य 8. किसी वस्तु व्यक्ति आदि के पहचान सूचक संबोधन का शब्द, संज्ञा 10. शवस्थल पर बनाया गया मकान, योग का अंतिम अंग, तपस्या 13. इंकार करना, ना कहना 14. पिता, क्लर्क, सम्मानीय व्यक्ति 15. आय पर लगने वाला टैक्स, इंकमटैक्स 16. प्रतिद्वंद्वी, प्रेमिका का दूसरा प्रेमी 17.

परंपरा, रीति, रिवाज 20. रूप से युक्त, चिह्न, लक्षण, नाटक, एक साहित्यिक अलंकार 23. लोग, प्रजा 25. नामी, नामवर, प्रसिद्ध 27. संसार का स्वामी, बादशाह, सम्राट, ईश्वर 28. फैलाना, खिंचाव पैदा करना।

ऊपर से नीचे

1. मारना, ग्रहण करना, आघात करना 2. मिथ्याअभिमान, आडंबर 3. विपत्ति, आफत 4. मालदार, धनवान, अमीर 5. ज्ञान

प्राप्त करना, अनुमान लगाना, कल्पना करना 7. हक 9. विवश, लाचार 11. मानकंद, नापने का पैमाना 12. अपमानित और तिरस्कृत 17. संतान उत्पन्न करने की क्रिया, जन्म देने की क्रिया 18. लंबे कपड़े का गट्टा, पशुओं को रखने की जगह 19. जलयान, वायुयान, जलपोत 21. आश्रय, सहारा 22. थोड़ा, जरा, तनिक 24. जुर्म, गुनाह 26. बाघ की तरह का धारीदार हिंसक एवं विशाल पशु।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 54 का हल

भू	कं	प		फा	य	दा		स
प		ल	ला	ट		य	ती	म
ति	ल	क		क	न	क		झ
	क्ष्म				रे			
ग	ण	क		सं	श	य		सौ
ह		या	च	क		म	न्न	त
रा	क्ष	स		र	क्ष	क		न
	त्रि				मि			
शा	य	री		का	त	र		गो

सलमान खान की मातृभूमि को सरकार से मिली मंजूरी!

सलमान खान की वॉर ड्रामा फिल्म मातृभूमि का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। नाम बदलने और टीजर पर आई प्रतिक्रियाओं से लेकर कई बार टलने के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। हालांकि, नई रिपोर्ट के मुताबिक अब ये सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। सब कुछ ठीक रहा तो मातृभूमि अगले महीने ही सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। मातृभूमि की कहानी पहले गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित थी। चीन के चित्रण को लेकर सरकार की मंजूरी को लेकर फिल्म पर असमंजस बना हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय फिल्म के नए वर्जन से संतुष्ट है और पिछले हफ्ते इसे एनओसी दे दी है। नया वर्जन पहले से काफी अलग है और इसमें भारत-चीन रिश्तों का सकारात्मक पहलू भी दिखाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने फिल्म के शुरुआती चीन-विरोधी रुख पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मातृभूमि के कई हिस्से दोबारा शूट किए गए। एक सूत्र ने बताया कि फिल्म का नया वर्जन पहले से काफी अलग है। इसमें अब भारत और चीन के रिश्तों को सकारात्मक नजरिए से भी दिखाया गया है। हालांकि, निर्माताओं ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, वहीं एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म की रिलीज तारीख भी तय हो चुकी है। सूत्र के अनुसार, सलमान अब इस साल 13 नवंबर को फिल्म रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। उनका मानना है कि दिवाली के बाद का माहौल इसके लिए एकदम सही रहेगा। हालांकि, अभी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। निर्माता जल्द ही फिल्म जमा करेंगे और अगर इसी महीने मंजूरी मिल जाती है तो फिल्म 13 नवंबर को सिनेमाघरों में आ जाएगी। अगले 10 दिनों में स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी।

अर्जुन रामपाल की 3 मंकीज का पहला मोशन-पोस्टर जारी!

अब्बास-मस्तान द्वारा निर्देशित और अर्जुन रामपाल के अभिनय वाली फिल्म 3 मंकीज लंबे समय से चर्चा में है। अब निर्माताओं ने इसका मोशन-पोस्टर जारी करते हुए कलाकारों की पहली झलक दिखाई है। यही नहीं, फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख का ऐलान भी किया गया है। इसमें अर्जुन का किरदार मनी हीस्ट के सर्जियो मार्किवना (प्रोफेसर) के किरदार से प्रेरित बताया जाता है। मुस्तफा बर्मावाला, विशाल जेठवा, प्रिया प्रकाश वारियर, अनिल बिश्नोई और दिवंगत टुनिशा शर्मा भी इसका हिस्सा हैं। 3 मंकीज एक हीस्ट-थ्रिलर है, जिसका निर्माण अल्लरखा वोहरा, फारुक वोहरा और सईद वोहरा ने एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बैनर तले किया है। फिल्म के मोशन-पोस्टर में अर्जुन को बंदूक पकड़े दिखाया गया है। उनके साथ 3 नकाबपोश लोग भी मौजूद हैं जो लुटेरों की तरह दिखते हैं। यह नजारा एक्शन और ड्रामा से भरपूर एक डकैती पर आधारित फिल्म जैसा दिखता है। इसे 4 दिसंबर, 2026 को भारत सहित दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

वैलेंटाइन पर सांपों की दुनिया दिखाएंगे कार्तिक आर्यन

कार्तिक आर्यन और करण जौहर साथ मिलकर फिल्म नागजिला पर काम कर रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स द्वारा निर्मित एक अनोखी क्रिएचर-कॉमेडी है, जिसका निर्देशन फुकरे फ्रैंचाइजी वाले मृगदीप सिंह लांबा ने किया है। आखिरकार अब कार्तिक अभिनीत नागजिला की नई रिलीज तारीख पर मुहर लगा दी गई है। कार्तिक अपनी नई फिल्म नागजिला के जरिए भारतीय लोककथाओं से प्रेरित, रूप बदलने वाले नागों की एक आकर्षक दुनिया लेकर आ रहे हैं। इसका दीदार वैलेंटाइन डे वीकेंड पर सिनेमाघरों में हो सकेगा, क्योंकि रिलीज तारीख 12 फरवरी, 2027 तय हुई है। फिल्म में अभिनेता पहली बार एक इच्छाधारी नाग के अनोखे अवतार में नजर आएंगे। साउथ अभिनेत्री प्रीति मुकुंदन इसके जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। वहीं रवि किशन विलेन के किरदार में दिखेंगे।

नानी और नितिन की नई फिल्म अलियास रुक्मिणी हुआ ऐलान

नानी और नितिन के प्रोजेक्ट एलियास रुक्मिणी की झलक सामने आई है। नेचुरल स्टार नानी एक दिलचस्प प्रोजेक्ट के लिए नितिन के साथ काम कर रहे हैं। आज मेकर्स ने फिल्म का टाइटल और उसकी एक झलक भी दिखाई। फिल्म का टाइटल एलियास रुक्मिणी रखा गया है, जो काफी दिलचस्प और रोमांचक है, और इसकी झलक ने सबका ध्यान खींचा है। धंधोरा फेम मुरली कांत देवसोथ इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत नानी के मुरली कांत देवसोथ से कहानी सुनाने के लिए कहने से होती है, और वे बताते हैं कि यह भगवान कृष्ण के बारे में है। इसके बाद गरम गोपाल, अमेकु अमे अंते इष्टम और ब्रथम वेंकत्रा जैसे नॉवेल्स के विजुअल्स दिखाए जाते हैं, और आखिर में नानी पूछते हैं कि रुक्मिणी कौन है। फिर चश्मा पहने नितिन सामने आते हैं और बताते हैं कि रुक्मिणी उनकी पत्नी हैं, और फिल्म का टाइटल एलियास रुक्मिणी सामने आता है।

हेली शाह का नवरात्र स्पेशल सॉन्ग गलगोटो रिलीज!

एक्ट्रेस हेली शाह इन दिनों अपने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं। ओटीटी शो चुंबक में कॉमेडी रोल में नजर आने के बाद अब हेली शाह का एक बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। वह फेस्टिव सॉन्ग गलगोटो में नजर आ रही हैं, जिसे नवरात्र सेलिब्रेशन से पहले रिलीज किया गया है। गाने में हेली शाह और देवर्षि शाह की जोड़ी दिखाई दे रही है, जबकि इसे मोनाली ठाकुर, पार्थ ओझा और सुहित अभ्यंकर ने अपनी आवाज दी है। गलगोटो को लेकर हेली शाह भी काफी एक्साइटेड हैं। एक्ट्रेस ने गाने के बारे में बात करते हुए कहा, इसे सुनते ही किसी का भी उठकर डांस करने का मन करने लगता है। इस गाने की शूटिंग का पूरा एक्सपीरियंस काफी एनर्जी से भरा हुआ था। मैं चाहती हूँ कि लोग इस गाने के साथ नवरात्र सेलिब्रेट करें और इसे खूब एंजॉय करें।

उन्होंने आगे कहा, गाने का म्यूजिक वीडियो भी फेस्टिव फील देता है। इसमें तेज बीट्स, एनर्जेटिक म्यूजिक और कलरफुल विजुअल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। नवरात्र के दौरान गरबा और डांस के माहौल को देखते हुए गाने की पूरी फील को काफी जश्न वाला रखा गया है।

गलगोटो को मोनाली ठाकुर, पार्थ ओजा और सुहित अभ्यंकर ने गाया है। गाने को सुहित अभ्यंकर ने कंपोज किया है, जबकि इसके लिрикस् जय तन्ना ने लिखे हैं। पीयूष शंकर ने गाने को प्रोड्यूस किया है। तीन अलग-अलग आवाजों के साथ तैयार किया गया यह ट्रैक म्यूजिक और



एनर्जी के मामले में काफी अलग है।

सिंगर मोनाली ठाकुर ने भी गलगोटो को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, यह गाना एनर्जी, रिदम और खुशी से भरा हुआ है। लोग इस गाने पर दिल खोलकर डांस करेंगे और इस साल नवरात्र में इसे अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा बनाएं।

वहीं टाइम्स म्यूजिक सीईओ मंदार ठाकुर ने कहा, नवरात्र देश के सबसे बड़े

कल्चरल सेलिब्रेशन में से एक है। गलगोटो में इसके लिए जरूरी एनर्जी, म्यूजिक और विजुअल अपील को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। गाने का फेस्टिव साउंड और इसका विजुअल ट्रीटमेंट नवरात्र के माहौल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

गलगोटो अब सभी बड़े ऑडियो प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहा है।

विक्की कौशल की महावतार में तारा सुतारिया!



चर्चा है कि विक्की कौशल के अपोजिट रोल के लिए तारा सुतारिया का नाम सबसे ऊपर चल रहा है।

अगर बात बन गई तो ये पहला मौका होगा, जब विक्की और तारा किसी फिल्म में साथ दिखाई देंगे। चर्चा तो ये भी है कि तारा ने इस फिल्म में खासी दिलचस्पी दिखाई है। फिल्म के निर्माता दिनेश विजान हैं। फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, महावतार की कास्टिंग को लेकर चर्चाएं पिछले कुछ समय से लगातार बदल रही हैं।

तारा का नाम भी निश्चित रूप से सामने आया है। निर्माता एक ऐसी अभिनेत्री को साइन करना चाहते हैं, जो फिल्म की इस भव्य व काल्पनिक दुनिया में अपनी मजबूत छाप छोड़ सके और तारा इस कसौटी पर खरी उतरती हैं।

तारा पिछली बार सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक में नजर आई थीं।

बता दें कि मैडॉक फिल्म्स के साथ छवा के बाद विक्की की ये दूसरी बड़ी फिल्म महावतार होगी, जिसकी शूटिंग जनवरी, 2027 में शुरू होने की उम्मीद है।

इस फिल्म में विक्की अमर और न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम का मुख्य और शक्तिशाली किरदार निभाते नजर आएंगे।

विशाल पैमाने पर बनने वाली इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है और इसके जरिए विक्की एक बार फिर अपने नए अवतार से पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं।

अभिनेता विक्की कौशल की आगामी पौराणिक फिल्म महावतार की हीरोइन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक, इस महा-फिल्म में लीड हीरोइन के रोल के लिए तारा सुतारिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। इससे पहले श्रद्धा कपूर और हरनाज संधू का नाम कपूर और पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू

के नाम भी रेस में थे, लेकिन अब तारा सुतारिया ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। हालांकि निर्माताओं की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।

निर्देशक अमर कौशिक की इस फिल्म से श्रद्धा कपूर और हरनाज संधू का नाम जुड़ने के बाद अब फिल्म गलियारों में

पीआरडी जवानों की 365 दिन रोजगार और समान कार्य-समान वेतन की मांग

संवाददाता

देहरादून। पीआरडी जवानों ने 365 दिन रोजगार और समान कार्य, समान वेतन की मांग की।

आज यहां लोहाघाट/चम्पावत/पौड़ी /टिहरी/चमोली/रुद्रप्रयाग/ आदि 13 जनपदों में सालभर रोजगार की गारंटी और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग पूरी नहीं होने से प्रांतीय रक्षक दल के जवानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। छह माह से अधिक समय बीतने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा एवं विभागीय मंत्री के द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं होने पर खासी नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर लंबित मांगों का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी दी कि विधानसभा चुनाव से पहले मांगों पूरी नहीं हुई तो उत्तराखंड का गरीब पीआरडी जवानों द्वारा ठोस रणनीति अपनाई जाएगी सरकार के खिलाफ। पीआरडी जवानों के अनुसार, 110 दिनों तक चले आंदोलन के बाद विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने उनकी मांगों के समाधान का आश्वासन दिया था। हालांकि, छह माह से अधिक समय गुजरने के बाद भी कोई ठोस राहत नहीं मिलने से जवानों में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष संजय पंवार ने कहा कि होमगार्ड जवानों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि पीआरडी जवान अब भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष रत हैं।

उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर संचालन, वाहन चलाने और सुरक्षा व्यवस्था, कुंभ मेला,आपदा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें सालभर रोजगार की गारंटी नहीं मिल पा रही है। नहीं उत्तराखंड के पीआरडी जवानों के परिवार का भविष्य सुरक्षित हों पा रहा है। प्रांतीय रक्षक संजय पंवार का कहना है कि सरकारी विभाग जरूरत के अनुसार उनकी सेवाएं लेते हैं, लेकिन रोजगार की निरंतरता और समान वेतन का मुद्दा अब तक लंबित है। रोजगार की अनिश्चितता के चलते उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रांतीय अध्यक्ष ने सरकार से केवल आश्वासन देने के बजाय उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय लेने की अपील की। उनका कहना है कि 365 दिन रोजगार और समान कार्य-समान वेतन की व्यवस्था लागू होने से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अधिक स्थिरता पुर्ण ईमानदारी निष्ठा भाव के साथ अपने ड्यूटियों का निर्वहन कर सकेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष संजय पंवार ने स्पष्ट किया कि मांगों का समाधान होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी दो सुत्रीय मांगें पूरी नहीं की गई, तो प्रदेशभर में रणनीति के तहत फिर से आंदोलन तेज किया जाएगा।

70 सीटों पर भाजपा का चुनावी चक्रव्यूह

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में 2०27 के विधानसभा चुनाव का रण अभी दूर है, लेकिन भाजपा ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। प्रदेश की सभी 7० विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा कर पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि वह चुनाव को अंतिम समय की कवायद नहीं, बल्कि लंबी राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ने की तैयारी में है। लक्ष्य साफ है लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी। मगर इस बार भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ जीत दोहराने की नहीं, बल्कि सत्ता विरोधी माहौल की आशंकाओं को मात देकर अपने चुनावी दावों को जमीन पर साबित करने की भी है।

सभी सीटों पर प्रभारियों की तैनाती के साथ भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड़ में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब विधानसभा स्तर पर पार्टी की गतिविधियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय समीकरणों और विपक्ष की रणनीति पर नजर रखने की जिम्मेदारी इन प्रभारियों के कंधों पर होगी। पार्टी के लिए यह व्यवस्था चुनावी तैयारियों की निगरानी का माध्यम बनेगी, लेकिन इसके साथ ही प्रभारियों की राजनीतिक क्षमता और संगठन में स्वीकार्यता की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने चुनावी लक्ष्य और जमीनी हकीकत के बीच तालमेल बैठाने की है। सत्ता में रहने के दौरान सरकार को अपने फैसलों, घोषणाओं और उपलब्धियों का हिसाब जनता के सामने देना पड़ता है। उत्तराखंड में बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उठे सवाल, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल सुविधाएं तथा भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के लिए सरकार को घेरने के प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। ऐसे में केवल संगठनात्मक नियुक्तियों और चुनावी नारों के सहारे सत्ता में वापसी

की राह आसान नहीं होगी। विधानसभा प्रभारियों को यह देखना होगा कि किन क्षेत्रों में पार्टी का संगठन मजबूत है और कहां स्थानीय असंतोष उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिन सीटों पर भाजपा को पिछले चुनावों में बढ़त मिली थी, वहां भी पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए नए सिरे से राजनीतिक जमीन तैयार करनी होगी। 7० विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति का एक अहम

◆2027 की जंग के लिए संगठन ने खोले पते, तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी

◆प्रभारियों के सामने सीट बचाने से लेकर विपक्ष की घेराबंदी तोड़ने तक की चुनौती

मकसद चुनाव से पहले विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करने के लिए संगठन को सक्रिय रखना भी है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को धार देने की कोशिश करेगी, जबकि क्षेत्रीय और अन्य राजनीतिक ताकतें स्थानीय असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास कर सकती हैं। भाजपा के सामने चुनौती केवल कांग्रेस को रोकने की नहीं, बल्कि उन विधानसभा क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाए रखने की होगी, जहां स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों को लेकर असंतोष या क्षेत्रीय मुद्दे चुनावी गणित बदल सकते हैं। उत्तराखंड में कई बार स्थानीय समीकरण और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता बड़े राजनीतिक दावों पर भारी पड़ते रहे हैं। इसलिए प्रदेश नेतृत्व की रणनीति का वास्तविक इम्तिहान विधानसभा स्तर पर ही होगा। विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि यह नेता संगठन को कितना सक्रिय कर पाते हैं। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की

पहुंच, स्थानीय समस्याओं की जानकारी, नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय तथा जनता के बीच सरकार की छवि को लेकर फीडबैक जुटाना उनकी भूमिका के अहम हिस्से होंगे। पार्टी के लिए सबसे जरूरी यह होगा कि चुनावी तैयारी कागजों और बैठकों तक सीमित न रहे। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जनता में असंतोष है या स्थानीय नेतृत्व को लेकर सवाल हैं, तो उनका समाधान चुनाव से पहले करना होगा। चुनाव के ऐन मौके पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कई बार देर से उठाया गया कदम साबित होती है।

भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में सत्ता में वापसी का दावा करना और उसे मतों में बदलना दो अलग-अलग बातें हैं। पार्टी के पास मजबूत संगठन और चुनावी प्रबंधन का अनुभव है, मगर विपक्ष को कमजोर मानकर चलना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। 7० सीटों पर प्रभारियों की घोषणा से भाजपा ने अपनी चुनावी मंशा जाहिर कर दी है। अब असली सवाल यह है कि क्या यह संगठनात्मक कवायद जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय नाराजगी दूर होगी? और क्या भाजपा सरकार के खिलाफ उठने वाले सवालों का प्रभावी जवाब तैयार कर सकेगी? फिलहाल भाजपा ने चुनावी बिसात पर अपने मोहरे सजा दिए हैं। अब मुकाबला संगठन की ताकत, सरकार के कामकाज और जनता के मूड के बीच होगा। 2०27 में तीसरी जीत का सपना तभी साकार होगा, जब पार्टी का चुनावी चक्रव्यूह जमीन पर असर दिखाएगा। वरना 7० सीटों पर प्रभारी तैनात करने का शक्ति प्रदर्शन भी चुनावी नतीजों की गारंटी नहीं बन पाएगा।

सेलाकुई में 700 मीटर लंबे इंटरलॉकिंग टाइल मार्ग निर्माण कार्य का किया विधिवत शिलान्यास

संवाददाता

देहरादून। सेलाकुई में 700 मीटर लंबे इंटरलॉकिंग टाइल मार्ग निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। आज यहां सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर द्वारा सेलाकुई स्थित गणेशप कैफे से बालकृष्ण के आवास तक लगभग 700 मीटर लंबे इंटरलॉकिंग टाइल मार्ग निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने कहा कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र का समग्र, संतुलित एवं सतत विकास उनकी प्राथमिकता है। क्षेत्र के प्रत्येक गांव, कस्बे एवं वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला होती हैं। बेहतर सड़क संपर्क से न केवल आवागमन सुगम होता है, बल्कि स्थानीय लोगों को दैनिक गतिविधियों में



भी सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि सेलाकुई क्षेत्र में आबादी के निरंतर विस्तार के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता भी बढ़ रही है। ऐसे में आंतरिक मार्गों का निर्माण एवं सुधार अत्यंत आवश्यक है। इंटरलॉकिंग टाइल्स से निर्मित होने वाला यह मार्ग क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्रदान करने के साथ ही स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जनहित से जुड़े विकास कार्यों का उद्देश्य केवल निर्माण कार्यों को पूरा करना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन को अधिक सुगम बनाना तथा विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। विधायक पुण्डीर ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

मार्गदर्शन एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास और जनकल्याण को निरंतर प्राथमिकता दी जा रही है। इसी भावना के अनुरूप सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनसुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं स्थानीय लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को आगे भी गति प्रदान की जाती रहेगी, ताकि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास के नए आयामों तक पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि व पार्षद अनिल नौटियाल, पार्षद श्रीमती कल्पना कोली, श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमती किरण पंवार, श्रीमती पूनम देवी, पंकज थापा, पूर्व प्रधान भगत सिंह राठौर, सभासद राजेश प्रधान तथा लोक निर्माण विभाग से सहायक अभियंता प्रवीण सक्सेना सहित अन्य गणमान्यजन एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

सू- दोकू क्र.055

	2			6			1	
3				4			2	
							6	
6					4			
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।

2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।

3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.54 का हल

8	7	6	9	5	1	2	3	4
1	3	9	2	8	4	5	6	7
4	5	2	3	7	6	9	1	8
2	8	5	4	6	7	1	9	3
3	1	7	8	9	2	4	5	6
6	9	4	1	3	5	7	8	2
9	4	1	6	2	8	3	7	5
7	2	8	5	1	3	6	4	9
5	6	3	7	4	9	8	2	1



गणेश जोशी ने जगद्गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज का स्वागत कर लिया आशीर्वाद

संवाददाता
देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जगद्गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज का स्वागत कर अशीर्वाद लिया।
आज यहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शारदीय नवरात्रि के अवसर पर अपने शासकीय आवास पर धर्मपत्नी निर्मला जोशी के साथ जगद्गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी भी उपस्थित रही।

दस पेटी शराब के साथ एक गिरफ्तार

संवाददाता
देहरादून। दस पेटी शराब के साथ एक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

मिली जानकारी के अनुसार अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए आबकारी विभाग की टीम ऋषिकेश एवं जनपदीय प्रवर्तन दल देहरादून की संयुक्त टीम के द्वारा आबकारी निरीक्षक श्रीमती प्रेरणा बिष्ट के नेतृत्व में मिली सूचना पर गडी श्यामपुर के पास एक चार पहिया वाहन हुंडई क्रेटा कार से अवैध शराब परिवहन करते 10 पेटी बरामद की गई जिसमें 100 बोतल रॉयल स्टैंग व्हिस्की एवं 24 बडवाइजर बियर बरामद हुई बरामद शराब की बोतलों पर चस्पा लेवल पर फॉर सेल डिफेंस पर्सनल ऑनली अंकित पाया गया। बरामद बीयर पर फॉर सेल इन चंडीगढ़ ओनली अंकित पाया गया, प्रथम दृष्टया जांचे जाने पर बोतलों पर लगे होलोग्राम एवं लेवल नकली है जिनकी जांच हेतु अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, वाहन चालक निशांत शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश को अवैध शराब परिवहन करने के जुर्म आबकारी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, तथा आबकारी क्षेत्र ऋषिकेश में अभियोग पंजीकृत किया गया। उससे अवैध शराब के संबंध में पूछताछ करने पर बताया गया कि यूपी मेरठ से यह शराब में डिफेंस के लेबल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आमजन को यह कैंटीन

प्रतिबन्धित नशीले कैप्सूलों के साथ 2 लोग गिरफ्तार

संवाददाता
देहरादून। पुलिस ने प्रतिबन्धित नशीले कैप्सूलों के साथ दो को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली डोईवाला पर गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के दौरान मिली सूचना पर लक्ष्मण मन्दिर रोड, हर्रावाला के पास से 02 सोवित कम्बौज को 216 प्रतिबन्धित कैप्सूल तथा पवन कुमार मिश्रा को 240 कैप्सूल (कुल 456 नशीले कैप्सूल) के साथ गिरफ्तार किया गया। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि बरामद कैप्सूलों को वह दोनों कलियर से खरीद कर लाए थे, जिन्हें वह नशे के आदी स्थानीय व्यक्तियों को ऊँचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में थे, गिरफ्तारों में से एक पूर्व में भी मादक पदार्थों/अवैध शराब की तस्करी में जेल जा चुका है।

चुनावी रण की तैयारी में जुटा भारत... << पृष्ठ 2 का शेष

आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों पर संतोष जताया और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित निर्वाचन योजना के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्तों, पुलिस रेंज के अधिकारियों, सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों ने भी हिस्सा लिया। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आयोग की यह कवायद संकेत देती है कि चुनावी मशीनरी को समय रहते सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, तैयारियों की वास्तविक परीक्षा चुनाव के दौरान होगी, जब प्रशासन को निष्पक्ष मतदान, कानून-व्यवस्था, मतदाता सुविधाओं और चुनावी आचार संहिता के पालन को एक साथ सुनिश्चित करना होगा।

तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो: धीरेंद्र प्रताप

संवाददाता
देहरादून। कांग्रेस के प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो।
आज यहां उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने एक विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनता से आह्वान किया और कहा तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो। उन्होंने भाजपा पर बोट चोरी और चंदा चोरी का आरोप लगाते हुए कहा अभी सरकार पर जनता का विश्वास उठ गया है भगवान राम के नाम की दुहाई देने वाले आज सबसे बड़े चोर साबित हुए हैं। धीरेंद्र प्रताप ने उत्तराखंड की बिगड़ती स्थिति कानून व्यवस्था पर चिंता और बेरोजगारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए उन्होंने जो सपने देखे देखे थे वह सपने टूट गए हैं। उन्होंने राज्य की तमाम सड़कों की खस्ता हालत पर निशाना

लगाते हुए कहा कि लोक निर्माण मंत्री अवलोक निर्माण को भूल गए हैं और इसका सड़कों की हालत ठीक हो इस और सरकार का ध्यान हट गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गगन बिहारी बताया और कहा मुख्यमंत्री अगर सड़कों पर चलते तो सड़कों की हालत अच्छा होती लेकिन मुख्यमंत्री सुबह ही हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं और जमीन पर क्या हो रहा है उसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। इस विशाल सम्मेलन को उनके अलावा रघुवीर सिंह बिष्ट, जंग बहादुर सिंह नेगी, गोपाल रावत, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र बिष्ट, गम्बर सिंह बिष्ट समेत अनेक नेताओं ने संबोधित किया और भाजपा की जन विरोधी नीतियों को निशाना बनाते हुए लोगों से आगामी चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। पिछले चार दिनों से लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे धीरेंद्र प्रताप ने इससे की खस्ता हालत को निशाना बनाया और

वहां पर कांग्रेस नेता नंदकिशोर नौटियाल के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह को संबोधित करते हुए कहा कि लोक निर्माण मंत्री विधायक रहते हुए क्षेत्र की सड़कों की खस्ता हालत को सुधारने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा यहां सड़कों में गढ़ा नहीं है गड्ढों में सड़क है। उन्होंने रिखणीखघल हल्दुखाल नैनीडांडा का दौरा किया और लोगों से जनसंपर्क कर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार देने का आह्वान किया और कहा 15 साल से यहां पर बने विधायक दिलीप रावत सिवाय विधायक निधि में अनियमिता करने के अलावा कोई भी विकास कार्य करने में विफल रहे हैं। उन्होंने उनके द्वारा महिलाओं में भांडे बर्तन बांटे जाने पर टिप्पणी करते हुए जनता को नया नारा देते हुए कहा नहीं चाहिए भांडे बर्तन अबकी बार चाहिए परिवर्तन और यह कहकर विधायक को इस बार जनता के द्वारा पराजित करने का आवाहन किया।

फिक्की फ्लो बाजार का आयोजन 16-17 अक्टूबर को

संवाददाता
देहरादून। फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन तृप्ति बेहल ने बताया कि फिक्की फ्लो बाजार का आयोजन 16 व 17 अक्टूबर को किया जायेगा।

आज यहां दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन तृप्ति बेहल ने कहा कि फ्लो बाजार उनके चैप्टर की प्रमुख पहलों में से एक है, जो उद्यमियों, डिजाइनरों, शिल्पकारों और व्यवसायों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने तथा व्यापक दर्शकों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष द वेडिंग एडिट थीम के अंतर्गत वह शादी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को एक मंच पर ला रहे हैं। इसमें फैशन और ज्वेलरी से लेकर गिफ्टिंग, डेकोर, ब्यूटी और अनूठे अनुभवों तक कई विकल्प शामिल होंगे। उन्हें उम्मीद है कि देहरादून के लोग खरीदारी उत्सव और नए अनुभवों से भरपूर इन दो दिनों का आनंद लेंगे। उन्होंने बताया कि आयोजन का उद्घाटन उत्तराखण्ड सरकार



के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी करेंगे। इसके अतिरिक्त दो दिवसीय बाजार में भाजपा की प्रदेश सचिव नेहा जोशी, पर्यटन विभाग की अपर निदेशक पूनम चंद, रीवा की राजकुमारी मोहेना कुमारी सिंह अभिनेत्री अरुणिका निशंक और फिक्की फ्लो की राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष डॉ. कुसुम अंसल सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। मीनाक्षी सोती ने बताया कि द वेडिंग एडिट थीम पर आधारित इस वर्ष के फ्लो बाजार में नौ प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। इनमें फैशन एवं अपैरल, ज्वेलरी, ब्यूटी एवं वेलनेस, होम डेकोर एवं लिविंग, गिफ्ट्स एवं फेवर्स, आर्ट्स, क्राफ्ट्स एवं हैंडक्राफ्टेड, फूड एवं गॉर्मे, वेडिंग सर्विसेज एवं

एक्सपीरियसेज तथा वॉडिंग वेन्यू एवं हास्पिटैलिटी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में स्थापित ब्रांड्स, उभरते डिजाइनों, हस्तनिर्मित उत्पादों के निर्माताओं और विशिष्ट व्यवसायों को एक साथ लाया जाएगा जिससे आंगतुकों को शादी, त्यौहारों और जीवनशैली से जुड़े खरीदारी के लिए एक विशेष अनुभव मिलेगा। स्मृति बत्ता ने कहा कि बाजार के पहले दिन नवरंग का आयोजन किया जाएगा। जो मां दुर्गा के नौ रंगों और नारी शक्ति के विभिन्न स्वरूपों को समर्पित है। यह पहल नारी को शक्ति, साहस, सौम्यता और विशिष्टता के नौ अलग-अलग गुणों का उत्सव मनाएगी। उन्होंने बताया कि फ्लो बाजार 2026 के माध्यम से फिक्की फ्लो उत्तराखण्ड का उद्देश्य महिला उद्यमियों, डिजाइनरों, शिल्पकारों और व्यवसायों को एक प्रभावी मंच प्रदान करना है ताकि उन्हें अपने उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करने, नेटवर्क विकसित करने और नए व्यावसायिक अवसर तलाशने का मौका मिल सके।

पूर्व अग्निवीरों को परिवहन विभाग में मिलेगा 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

हमारे संवाददाता
हरिद्वार। उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में धामी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में हुई कैबिनेट बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। पूर्व में निर्धारित 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के साथ भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। इसका लाभ परिवहन विभाग सहित विभिन्न विभागों के समूह 'ग' के वर्दीधारी पदों पर मिलेगा। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के विभाग से जुड़े इस निर्णय से पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवा में आने के अवसर मिलेंगे। संबंधित

त विभागों में गृह, वन, परिवहन, आबकारी और सचिवालय प्रशासन शामिल हैं। नई नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट देने की व्यवस्था की गई है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने

◆परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने धामी सरकार के फैसले को सराहा

इस फैसले को युवाओं और देश की सेवा कर चुके अग्निवीरों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सेना में सेवा देने के बाद प्रदेश लौटने वाले युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें और उनके अनुभव तथा अनुशासन का लाभ राज्य को भी

प्राप्त हो। बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में छूट की व्यवस्था उन्हें सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी। इससे युवाओं को अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। प्रदीप बत्रा ने प्रथम मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना देश की रक्षा व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से पूर्व अग्निवीरों के कौशल, प्रशिक्षण और अनुभव का उपयोग समाज तथा प्रदेश के विकास में किया जा सकता है।

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ

◆प्रीतम सिंह एवं डॉ. हरक सिंह रावत की उपस्थिति में ली कांग्रेस की सदस्यता



हमारे संवाददाता
देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह एवं प्रदेश चुनाव प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत की गरिमामयी उपस्थिति में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, राजीव भवन, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व तथा कांग्रेस पार्टी की रीति-नीतियों एवं सिद्धान्तों में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति

अध्यक्ष प्रीतम सिंह एवं चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं का फूल मालाओं एवं कांग्रेस का पटका पहनाकर स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई तथा उनके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि देश की आजादी, लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता एवं सर्वधर्म समभाव की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला विशाल जनआन्दोलन है।
चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देशभर में

लोकतंत्र, संविधान और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए निरन्तर संघर्ष कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और जनहित के मुद्दों के प्रति लोगों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। इसी का परिणाम है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पलायन जैसे ज्वलन्त मुद्दों पर सरकार के पास कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब भाजपा के खोखले वादों और झूठी घोषणाओं से ऊब चुकी है तथा कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता एवं मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार में नए नेताओं के शामिल होने से पार्टी का जनाधार और अधिक मजबूत होगा तथा भाजपा सरकार के विरुद्ध चल रहे जनसंघर्ष को नई गति मिलेगी।

जयपुर में हाईजैक अलर्ट के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग!

संवाददाता

नई दिल्ली। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक होने के अलर्ट के बाद हड़कंप मच गया। एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2030 की जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जा रहा था। जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद एयर ट्राफिक कंट्रोल (एटीसी) को विमान को लेकर अलर्ट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं। बताया जा रहा है कि विमान से कथित तौर पर स्कॉड 7500 सिग्नल प्रसारित हुआ था। विमानन क्षेत्र में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ट्रांसपोंडर कोड है, जिसका उपयोग पायलट किसी संभावित हाईजैकिंग या विमान में अवैध हस्तक्षेप की स्थिति की जानकारी एयर ट्राफिक कंट्रोल को गोपनीय तरीके से देने के लिए करते हैं। इसी संकेत के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं और विमान की प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालकर एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्धारित सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया गया। किसी के घायल होने या किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विमान से हाईजैक अलर्ट क्यों प्रसारित हुआ। यह तकनीकी त्रुटि थी, गलत संकेत था या फिर किसी अन्य कारण से यह कोड सक्रिय हुआ, इसकी जांच की जा रही है।



इससे पहले 30 सितंबर 2026 को दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रही फ्लाईडुबई की फ्लाइट से भी हाईजैक अलर्ट आया था। बोइंग 737 मैक्स विमान ने पहले इमरजेंसी कोड 7700 और फिर कुछ समय के लिए स्काक-7500 जारी किया। इसके बाद विमान का रास्ता बदला गया और सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस घटना में विमान के ओमानी को-पायलट पर पायलट पर हमला करने और विमान को तेल अवीव एयरपोर्ट के टर्मिनल से टकराने की कोशिश करने का आरोप है।

युवक ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार

हमारे संवाददाता
पौड़ी। पुलिस ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए युवक की पहचान सूरज (उम्र 22 वर्ष) पुत्र मोहनलाल, निवासी धुमाकोट, जनपद पौड़ी गढ़वाल, के रूप में हुई है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर धारा 137(2), 5(र)(पप)/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर उसे न्यायालय में भेजा गया है। 2 अक्टूबर को धुमाकोट निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना धुमाकोट में तहरीर दी गई कि सूरज निवासी चामसैण, धुमाकोट ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। तहरीर के आधार पर थाना धुमाकोट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी। जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नामजद आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।



तिरंगा लहराना अपराध नहीं, जंतर-मंतर वापस हासिल करेंगे : राहुल गांधी

संवाददाता

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने इसके लिए युवाओं को जेल में डालने की कार्रवाई को कायरता बताया। अपने संदेश में राहुल गांधी ने छात्रों, युवाओं, पत्रकारों और इण्डिया गठबंधन का उल्लेख करते हुए कहा कि भले ही सभी अलग-अलग बैनर के तहत अपनी बात रख रहे हों, लेकिन उनकी मांग एक है। उन्होंने प्रदर्शन को नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया और जंतर-



मंतर को जनता के लिए फिर से हासिल करने की बात कही। उनका संदेश था कि प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार लेकर रहेंगे। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। सीजेपी और विपक्षी दलों का कहना है कि

लोकतंत्र में असहमति जताने और शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जगह मिलनी चाहिए। दूसरी ओर, पुलिस ने अपनी कार्रवाई के पीछे स्थल पर लागू प्रतिबंधों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी आशंकाओं का हवाला दिया है।

सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के बीच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी आंदोलन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र से दिल्ली रवाना हो गए हैं। उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि वह बुधवार को दिल्ली पहुंचेंगे और प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। दीपके ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें रास्ते में रोका गया, तो वह उसी जगह से विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ आंदोलन जारी रखने और देशभर में विरोध प्रदर्शन खड़े करने की बात भी कही है।

भूमि धोखाधड़ी मामले में दो साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

हमारे संवाददाता
देहरादून। भूमि धोखाधड़ी के मामले में दो साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
जानकी के अनुसार जून 2024 को अरुण कुमार निवासी 2268 सेक्टर 28 फरीदाबाद हरियाणा ने कोतवाली विकासनगर पर तहरीर देकर बताया था कि गुरुबचन निवासी विकासनगर, मनुष निवासी ढकरानी, कमल सिंह निवासी वंशीपुर ढकरानी, चमन कुमार निवासी बाबूगढ़ विकासनगर तथा पूरण सिंह निवासी सदर बाजार सहारनपुर द्वारा उनका फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा

कर उनकी भूमि का फर्जी मुख्तारनामा तैयार करते हुए उसे किसी अन्य को विक्रय कर दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी।
उक्त मुकदमे में वादी के स्थान पर मुख्तारनामे में फर्जी अरुण कुमार बना अभियुक्त अभियोग पंजीकृत होने के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था, जिसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु पुलिस द्वारा अभियुक्त के फर्जी आधार कार्ड में इस्तेमाल किये गये फोटो को नेट ग्रिड पोर्टल में अपलोड किया गया तथा नेट ग्रिड के माध्यम से उक्त फोटो से मिलते-जुलते व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी के आधार पर

प्रत्येक व्यक्ति को तस्दीक किया गया तो उक्त फोटो की सही पहचान उदित कुमार वर्मा पुत्र सुरेन्द्र कुमार वर्मा, निवासी धोबी घाट, तोता चौक, सिवेन्द्र विहार कॉलोनी, थाना मंडी, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई, जिस पर तत्काल एक टीम को सहारनपुर रवाना कर प्रकाश में आये अभियुक्त उदित कुमार उपरोक्त को दिनांक- 13/10/2026 को पुलिस द्वारा मण्डी क्षेत्र सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह पूर्व में वह सुनार का काम करता था तथा चांदी का सामान बेचने के सिलसिले में अक्सर विकासनगर, सहसपुर एवं सेलाकुई क्षेत्र में आता-जाता रहता था। इसी दौरान उसकी पहचान

गुरुबचन सिंह उर्फ बब्बू सरदार से हुई थी। गुरुबचन सिंह द्वारा उसे हरबर्टपुर में स्थित एक जमीन, जो हरियाणा निवासी एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज थी, के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उसे उक्त जमीन का फर्जी मालिक बनकर मुख्तारनामा तैयार करवाने तथा उसके एवज में उसे मोटी धनराशि देने का लालच दिया गया। जिस पर उसके द्वारा गुरुबचन सिंह व उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर भूमि के मूल मालिक अरुण कुमार के नाम का फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज तैयार किये गये तथा आधार कार्ड में अभियुक्त द्वारा असली अरुण कुमार के स्थान पर अपनी फोटो का इस्तेमाल किया गया।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।